Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to categorise yarn manufactured by Solar Charkha as 'Khadi' -laid.

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): मै माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जी का ध्यान देशभर में सोलर चरखा से निर्मित सूत को खादी का दर्जा दिए जाने से सम्बंधित लोक अविलम्बनीय विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

विदित है कि सर्वप्रथम जून 2018 में, MSME मंत्रालय, भारत सरकार ने मिशन सोलर चरखा" की शुरुआत की थी, जो भारतीय हरित खादी ग्रामोदय संस्थान के द्वारा नवादा (बिहार) में लागू किया गया था तथा एक सफल पायलट परियोजना बनी । इस मिशन के तहत, भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपये के बजट के साथ 50 सौर चरखा समूहों को मंजूरी दी थी । मिशन सौर चरखा के पीछे का लक्ष्य ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करना था । उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैंने खादी की अवधारणा में "सौर चरखा" के प्रभाव और महत्व को देखा था एवं सोलर चरखे में ग्रामीण भारत, खासकर महिलाओं के बड़ी संख्या में आजीविका के अवसर पैदा करने का कौशल, पैमाना और गति को समझा था ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं पलायन एक बड़ा मुददा है एवं गाँव में रहने वाले कई ऐसे लोग है जो शिल्पकार भी है, लेकिन बेहतर प्रशिक्षण एवं उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें बेरोजगारी में रहना पड़ता है।

मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी (जो कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कर्मक्षेत्र होने के साथ-साथ जयप्रकाश नारायण जी के आन्दोलन का केंद्र-बिंदु भी था) के सेवापुरी में केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 500 सोलर चरखा एवं 100 लूम लगाए गए, जिसका सफल संचालन रहा है, जिसमे बड़ी संख्या में महिलाओं एवं युवाओ को स्वरोजगार का अवसर मिला । उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा भी सोलर चरखे

को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इससे निर्मित धागे को खादी का दर्जा दिया गया है । अगर भारत सरकार के द्वारा सोलर चरखे से निर्मित धागे को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश में खादी का दर्जा दिया जाता है तब यह निर्णय सम्पूर्ण भारत में एक ऐतिहासिक निर्णय होगा और वह ग्रामीण क्षेत्रो से शहरो में हो रहे पलायन को रोकने एवं स्व रोजगार से लोगो को जोड़ने के साथ-साथ एक नवीन भारत के निर्माण में भी सहायक होगा ।

अत: माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जी के साथ-साथ भारत सरकार से मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रो में बढती बेरोजगारी के चलते शहरो की ओर लगातार हो रहे पलायन को रोकने तथा स्वरोजगार के अवसर को बढाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया सोलर चरखा मिशन के तहत सौर चरखा से निर्मित धागे को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर खादी का दर्जा दिया जाए ।